

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. विशेष अपील रिट याचिका संख्या 493/2024

- राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय कक्ष संख्या 307, तीसरी मंजिल, विद्युत विनायक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302005, राजस्थान में स्थित।
- मुख्य अभियंता, आरआरवीयूएनएल, कक्ष संख्या 307, तीसरी मंजिल, विद्युत विनायक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर - 302005, राज.
- उप मुख्य अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कक्ष संख्या 307, तीसरी मंजिल, विद्युत विनायक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर - 302005, राज. या पांचवीं मंजिल, ड्रेमैक्स प्लाजा, सहकार मार्ग- 302001

----अपीलकर्ता

बनाम

- सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4 एफ-15, ओलिवर हाउस, न्यू पावरहाउस रोड, जोधपुर (राजस्थान) में स्थित।
- एनआरसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9 वीं मील का पत्थर, कश्मीर रोड, वेरका, अमृतसर-143501 में स्थित।
- राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान के माध्यम से।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री कार्तिक सेठ के साथ श्री दर्श पारीक और श्री केशव पाराशर
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए	:	श्री सुशील डागा के साथ श्री अनुराग कलावतिया के साथ श्री चित्रांश माथुर और सुश्री पारुल सिंघल
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए	:	श्री पुनीत सिंघवी के लिए श्री समीर सोढी

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

निर्णय

दिनांक 19/11/2024 को सुनाया गया

(माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा):

1. यह अपील विद्वान अवकाशकालीन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 25.06.2024 को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) के पक्ष में एक एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया गया है। यह आदेश अपीलकर्ताओं (रिट याचिका में आधिकारिक प्रतिवादी) को दिनांक 10.06.2024 के आशय पत्र और दिनांक 07.12.2023 की निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसरण में यहां प्रतिवादी संख्या 2 (रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 5) को कार्य आदेश जारी करने से रोकता है।
2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान अवकाशकालीन न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को सुने बिना और महत्वपूर्ण तथ्यों को उनके संज्ञान में लाए बिना ही एक एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर दिया। अपीलकर्ताओं ने 10.07.2024 को स्थगन आदेश रद्द करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण आधारों पर एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, शीघ्र निपटान के लिए कई प्रार्थनाओं के बावजूद, यह आवेदन लंबित रहा। इसलिए, उक्त अंतरिम आदेश को एक अपील दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसका निपटान 06.08.2024 को विद्वान एकल न्यायाधीश से यह अनुरोध करते हुए किया गया था कि वे स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन को जल्द से जल्द, अधिमानतः एक सप्ताह की अवधि के भीतर सुनें। हालांकि, बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद आवेदन पर विचार नहीं किया गया। इसलिए, अपीलकर्ता ने अपील की बहाली और गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार करने के लिए एक आवेदन दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दिनांक 21.09.2024 के आदेश द्वारा, इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया और अपील को उसके मूल संख्या पर बहाल कर दिया गया।
3. गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामला कन्वेयर बेल्ट की आपूर्ति के लिए कार्य प्रदान करने से संबंधित है, जो थर्मल संयंत्रों में बॉयलर

तक कोयले के परिवहन के लिए अत्यंत आवश्यक है और समय पर कन्वेयर बेल्ट की खरीद में विफलता से गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होंगी, जिसके परिणामस्वरूप थर्मल बिजली उत्पादन रुक जाएगा और राज्य में बिजली की आपूर्ति में बाधा आएगी। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि विद्वान अवकाशकालीन न्यायाधीश को अपीलकर्ताओं को सुने बिना एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने अनुबंध प्रदान करने की कार्यवाही की और प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में आशय पत्र जारी किया। चूंकि वह न्यूनतम बोलीदाता था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 को न्यूनतम बोलीदाता के रूप में अनुबंध प्रदान करने का निर्णय राजकोषीय विवेक पर आधारित था, जिसमें मामले के पूरे पहलू पर विचार किया गया था, विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि कथित प्रतिबंध की अवधि के दौरान, वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 3 को एनटीपीसी द्वारा ही आपूर्ति आदेश दिए गए थे, जिसमें न्यूनतम बोलीदाता/प्रतिवादी संख्या 3 के कार्य निष्पादन पर विचार किया गया था। इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई स्पष्ट मनमानी नहीं थी जो हस्तक्षेप को उचित ठहराती। निविदा मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात की सराहना नहीं की कि केवल तकनीकी आधार पर, खरीद को रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एन.जी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम विनोद कुमार जैन और अन्य [2022(6) एससीसी 127] के निर्णय सहित विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं के मामलों में, निषेधाज्ञा हल्के ढंग से नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने निवेदन किया कि स्थगन आदेश रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के बाद भी, उनके आवेदन पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है और इसलिए, अपीलकर्ता, जो एक लोक पदाधिकारी है, के पास इस अपील के माध्यम से एकपक्षीय अंतरिम आदेश को चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने निवेदन किया कि अंतरिम आदेश को तत्काल रद्द करने की आवश्यकता है क्योंकि जून 2024 में आशय पत्र जारी होने के बावजूद कन्वेयर बेल्ट की खरीद रुकी हुई है। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का

उल्लेख करते हुए, उन्होंने निवेदन किया कि विभिन्न बिजली परियोजनाओं को कन्वेयर बेल्ट की सख्त आवश्यकता है और यदि उन्हें समय पर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं जो बिजली उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी और सार्वजनिक हित के विपरीत होंगी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अपीलकर्ता रिट याचिका के शीघ्र अंतिम निपटान के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए, अंतरिम आदेश को रद्द किया जा सकता है और कोई भी खरीद रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन की जा सकती है।

प्रतिवादी संख्या 2-न्यूनतम बोलीदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के मामले का समर्थन किया और कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 ने भी स्थगन आदेश रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। वह भी उसके विरुद्ध पारित एकपक्षीय अंतरिम आदेश से व्यथित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार योग्य है क्योंकि एनटीपीसी ने उसे 02.07.2020, 23.07.2020 और 27.07.2020 को खरीद आदेश जारी किए थे, जिसका अर्थ है कि 01.04.2020 से 08.08.2020 तक एनटीपीसी द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 09.08.2023 के बाद, एनटीपीसी ने 28.11.2023 को कन्वेयर बेल्ट की आपूर्ति के लिए फिर से खरीद आदेश दिया, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान एनटीपीसी को सेवाएं प्रदान कर रहा था। वह एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड आदि जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान कर रहा है। साउथ ईस्टर्न कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी दिनांक 13.04.2022 के खरीद आदेश, सिंगा रानी कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी दिनांक 24.06.2023 के खरीद आदेश, अपीलकर्ता द्वारा जारी दिनांक 27.01.2020 के कन्वेयर बेल्ट की आपूर्ति के लिए खरीद आदेश का संतोषजनक ढंग से पालन किया गया था और कोई शिकायत नहीं थी। यह नहीं कहा जा सकता कि उसे पूरी अवधि के संबंध में आपूर्ति के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था।

अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दोनों ने रिकॉर्ड पर मौजूद विभिन्न खरीद आदेशों और अन्य प्रमाणपत्रों और संचारों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने समय-समय पर

संबंधित खरीद आदेशों के विरुद्ध पूरी सामग्री की आपूर्ति की और वे सभी बेल्ट संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं और ऐसी आपूर्ति आदेशों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति उठाई, यह प्रस्तुत करते हुए कि एक बार जब इस न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश से स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध करते हुए एक आदेश पारित किया था, तो केवल इसलिए कि आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय नहीं लिया जा सका और वह लंबित रहा, दिनांक 06.08.2024 को पारित पूर्ववर्ती आदेश को संशोधन आवेदन की आड़ में वापस नहीं लिया जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने स्थगन आदेश रद्द करने के लिए अपने आवेदन पर जोर देने के बजाय, बार-बार अपीलीय न्यायालय की अनुग्रह की मांग की है, जो उचित नहीं है। अपीलकर्ताओं का उपाय विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष स्थगन आदेश रद्द करने के लिए अपने आवेदन पर जोर देना है। इस तर्क के समर्थन में कि संशोधन के लिए आवेदन विचारणीय नहीं था और इसलिए, विचारणीय न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य था, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड [2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 313] और दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह अर्बन और अन्य [(2000) 7 एससीसी 296] के मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

यह भी तर्क दिया गया है कि अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम 134 के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर विचारणीय नहीं है, क्योंकि विद्वान अवकाशकालीन न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न तो अंतिम आदेश है और न ही इसे निर्णय कहा जा सकता है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने सफल बोलीदाता यानी एनआरसी इंडस्ट्रीज/प्रतिवादी संख्या 3 के साथ अपीलकर्ताओं की मिलीभगत का भी आरोप लगाया, यह प्रस्तुत करते हुए कि जब मामला 09.10.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, तो निजी प्रतिवादी संख्या 3 भी उसे कोई नोटिस जारी किए बिना उपस्थित हुआ था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि

अपीलकर्ता स्थगन आदेश रद्द करने के लिए अपने आवेदन का गंभीरता से पीछा नहीं कर रहे हैं।

गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि नियमों और शर्तों के खंड-III के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 2 योग्य नहीं था क्योंकि उसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी एनटीपीसी अनुमोदित विक्रेता घोषित नहीं किया जा सका था और पिछले सात वर्षों के दौरान किसी भी एनटीपीसी/सरकार/अर्ध-सरकारी/पीएसयू/बीएसई या एनएसई सूचीबद्ध कंपनी को आवश्यक कन्वेयर बेल्ट की आपूर्ति नहीं की थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 को एनटीपीसी द्वारा 10.08.2020 से 09.08.2023 तक तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अंतरिम आदेश पारित करते समय विद्वान अवकाशकालीन न्यायाधीश ने इस पर विचार किया था। प्रतिवादी संख्या 3 को निविदा प्रदान करना, प्रतिबंधित इकाई होने के बावजूद, स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं द्वारा उसके पक्ष में अनुचित पक्षपात दर्शाता है, जो सार्वजनिक हित के विपरीत है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को केवल इस आधार पर निविदा प्रदान करने में मनमानी है कि वह न्यूनतम बोलीदाता है। रमाना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य [(1979) 3 एससीसी 489], मोनार्क इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम कमिश्नर, उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अन्य [एआईआर 2000 एससी 2272], मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम द स्टेट ऑफ कर्नाटक और अन्य [एआईआर 2012 एससी 2915], सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य बनाम एसएलएल-एसएमएल (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम) और अन्य [(2016) 8 एससीसी 622] और सीजेडएआरसीएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बनाम राइट्स लिमिटेड और अन्य [डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 1039/2021] दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के अनिल कुमार श्रीवास्तव बनाम शौर्य सुनील और अन्य [एससीसी ऑनलाइन पैट 21] के मामले में भी निर्णय पर भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अंतः-न्यायालय अपील की सुनवाई करते समय, अपीलीय न्यायालय एकल पीठ के आदेशों या निर्णयों पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 दोनों ने दिनांक 07.12.2023 की निविदा सूचना के अनुसरण में निविदा प्रस्तुत की। जबकि रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 दूसरा न्यूनतम बोलीदाता था, प्रतिवादी संख्या 2 न्यूनतम बोलीदाता के रूप में उभरा। अपीलकर्ताओं ने 10.06.2024 को उसके पक्ष में आशय पत्र जारी करने की कार्यवाही की। प्रतिवादी संख्या 1 ने एक रिट याचिका दायर करके इसे चुनौती दी है। विद्वान अवकाशकालीन न्यायाधीश ने दिनांक 25.06.2024 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं को आशय पत्र के अनुसरण में कार्य प्रदान करने से रोकने वाला अंतरिम आदेश पारित किया। उपरोक्त आदेश अपीलकर्ताओं या सफल बोलीदाता को सुने बिना एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था। अपीलकर्ता आरवीवीएनएल, जो एक बिजली आपूर्ति कंपनी है, ने 10.07.2024 को एकपक्षीय स्थगन आदेश रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, जब विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई, तो अपीलकर्ताओं ने डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 493/2024 के रूप में रिट अपील दायर की। पहली बार में, यह न्यायालय अपने गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए इच्छुक नहीं था, हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि अंतरिम आदेश एकपक्षीय प्रकृति का था और अपीलकर्ताओं ने 10.07.2024 को स्थगन आदेश रद्द करने के लिए पहले ही एक आवेदन दायर कर दिया था, जो लंबित था, अपील को शुरू में दिनांक 06.08.2024 के आदेश द्वारा निपटाया गया था, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश से स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन को जल्द से जल्द, अधिमानतः एक सप्ताह की अवधि के भीतर सुनने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी कारण से, आवेदन लंबित रहा। जब स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई और मामला अपीलकर्ता आरवीवीएनएल के खिलाफ अंतरिम आदेश के साथ लंबित रहा, तो उसने अपील की बहाली के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार किया जा सके। 21.09.2024 को, विविध आवेदन संख्या 281/2024 को स्वीकार कर लिया गया और अपील को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए उसके मूल संख्या पर बहाल कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई है।

7. अपील की विचारणीयता के संबंध में सबसे पहली आपति इस आधार पर आधारित है कि संशोधन आवेदन विचारणीय नहीं था। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां संशोधन आवेदन विचाराधीन है। संशोधन के लिए आवेदन पर विचार किया गया था और इसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2024 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अपील को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए उसके मूल संख्या पर बहाल कर दिया गया है। इसलिए, इन कार्यवाहियों में, दिनांक 21.09.2024 के आदेश की शुद्धता और वैधता को आनुषंगिक रूप से चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, इस आधार पर अपील की विचारणीयता के संबंध में आपति खारिज की जाती है और इस पहलू पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

8. अपील की विचारणीयता के संबंध में एक और आपति इस आधार पर टिकी है कि राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1951 का नियम 134 अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करता है। यह तर्क गलत है क्योंकि नियम 134 में निहित प्रावधान अपीलीय क्षेत्राधिकार को केवल निर्णयों या अंतिम आदेशों तक सीमित नहीं करते हैं, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। अपील निर्णय और आदेश के खिलाफ विचारणीय है। आदेश में अंतरिम आदेश भी शामिल है। यह सच है कि अंतरिम आदेश के खिलाफ रिट अपील में हस्तक्षेप का दायरा अत्यंत सीमित है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अपील बिल्कुल भी विचारणीय नहीं है। इस संबंध में भी तर्क खारिज किया जाता है।

9. चूंकि अपील की विचारणीयता के संबंध में अगला निवेदन अपील की अविचारणीयता पर आधारित है, इसलिए अन्य निवेदन से निपटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलीय न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर कोई पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है। वर्तमान एक अंतः-न्यायालय अपील है और इसलिए, यह स्पष्ट रूप से विचारणीय है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपीलकर्ता, जो बिजली की आपूर्ति और वितरण के लिए सार्वजनिक कार्यों से अधिदेशित एक निगम है, केवल स्थगन आदेश रद्द करने के लिए अपने आवेदन पर अनुग्रह की मांग के लिए बार-बार गुहार लगा रहा है। विद्वान अवकाशकालीन न्यायाधीश ने 25.06.2024 को एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि अपीलकर्ताओं ने

10.07.2024 को स्थगन आदेश रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन अनुरोध करने के बावजूद आवेदन लंबित रहा, इतना अधिक कि अपीलकर्ताओं को एकपक्षीय अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। शुरू में, हम अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि स्थगन आदेश रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया गया था और विचाराधीन था। इसलिए, हमने विद्वान एकल न्यायाधीश से स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का अनुरोध करते हुए अपील का निपटान किया। हालांकि, आवेदन पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है और इसलिए अपीलकर्ताओं ने फिर से न्यायालय की अनुग्रह की मांग की है।

10. एक बार जब एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित हो जाता है, तो जैसे ही स्थगन आदेश रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, आवेदन पर शीघ्रता से एक या दूसरे तरीके से निर्णय लेना आवश्यक होता है और इसे लंबे समय तक लंबित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहां यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता ने कन्वेयर बेल्ट की खरीद के मामले में अनुबंध प्रदान करने को चुनौती दी है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के संज्ञान में सही ढंग से लाया है कि कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कन्वेयर बेल्ट की समय पर खरीद बिल्कुल आवश्यक है, जिससे बिजली का उत्पादन और राज्य में उपभोक्ताओं को उसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसलिए, ऐसे मामलों में, आमतौर पर एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था और यदि इसे दिया भी गया था, तो स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन पर शीघ्रता से विचार किया जाना आवश्यक था या रिट याचिका पर ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए था। हम पाते हैं कि 10.06.2024 को पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहा है जिसके परिणामस्वरूप कन्वेयर बेल्ट की खरीद में देरी हो रही है।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि चुनौती का मुख्य आधार न्यूनतम बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करना है, हालांकि वह योग्य नहीं था क्योंकि उसे विचाराधीन अवधि के संबंध में एक प्रतिबंध आदेश का सामना करना पड़ा था। अपीलकर्ताओं ने विवरण प्रस्तुत किया है कि तकनीकी और वित्तीय बोलियों पर विचार करते समय विभिन्न बैठकों में इस पहलू

से कैसे निपटा गया और प्राधिकरण ने इस बात पर विचार किया कि ऐसे आदेशों के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 2 ने एनटीपीसी को कन्वेयर बेल्ट की आपूर्ति जारी रखी। विशेषज्ञों ने प्रतिवादी संख्या 2 की कार्य निष्पादन रिपोर्ट भी प्राप्त की है और रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद, न्यूनतम बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

12. इस रिट अपील में, हम मामले की गुण-दोष के आधार पर आगे जांच नहीं करेंगे क्योंकि यह विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है। हालांकि, मामले के इन पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। एन.जी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिनियम 18 ऑफ 2018 द्वारा धारा 41 में डाले गए खंड (एच) (ए) में निहित प्रावधानों के आलोक में इस प्रकार अवलोकन किया:

"21. चूंकि सड़क का निर्माण एक बुनियादी ढांचा परियोजना है और विधायिका के इरादे को ध्यान में रखते हुए कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोका नहीं जाना चाहिए, उच्च न्यायालय को बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण को रोकने के लिए अपने हाथ खींचने की सलाह दी जाती। ऐसे प्रावधानों को रिट न्यायालय द्वारा भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके लॉर्डशिप ने ऐसे मामलों में निषेधाज्ञा देने के खिलाफ चेतावनी दी। निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गई हैं:

"26. यहां एक सावधानी का शब्द उल्लेख किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक सेवा के किसी भी अनुबंध में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में, बड़ी सार्वजनिक भलाई के लिए सेवाओं की पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने वाला कोई अंतरिम आदेश नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने से किसी को भी मदद नहीं मिली है सिवाय एक ठेकेदार के जिसने अनुबंध बोली खो दी और इससे राज्य को नुकसान हुआ है, किसी को भी कोई तदनुरूपी लाभ नहीं हुआ है।"

13. इसलिए, हमारा विचार है कि एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। यदि इसे दिया भी गया था, तो स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन पर जैसे ही इसे दायर किया गया था, निर्णय लिया जाना चाहिए था। किसी भी मामले में, यह

कन्वेयर बेल्ट की खरीद का मामला होने के कारण, जो बिजली उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, याचिका पर ही जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना आवश्यक था, एक बार जब अंतरिम आदेश दिया गया था। स्थगन आदेश रद्द करने के आवेदन पर सुनवाई किए बिना अंतरिम आदेश जारी रखना और मामले को लंबित रखना, वस्तुतः याचिका को स्वीकार करने के बराबर है। पक्षों के अधिकारों के अलावा, कन्वेयर बेल्ट की खरीद में छह महीने की देरी ने बिजली उत्पादन को गंभीर और प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

हालांकि, यह देखते हुए कि अंतरिम आदेश 25.06.2024 से लागू है, रिट याचिका पर ही एक महीने के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए। सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी पक्ष को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश को तीन दिनों के भीतर विद्वान एकल पीठ के संज्ञान में लाया जाएगा। दिनांक 25.06.2024 का अंतरिम आदेश एक और महीने की अवधि के लिए या रिट याचिका में निर्णय तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा और उसके बाद यह अपनी प्रभावकारिता खो देगा।

14. तदनुसार अपील को उपरोक्त तरीके और सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), न्यायमूर्ति (मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), मुख्य न्यायमूर्ति
मोहितटक /

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

